

पहले मुख्य समाचार।

- वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत।
- भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ लागू। प्रदेश के लेदर और फुटवियर सहित दूसरे उत्पादों के लिए मिलेगा बड़ा बाजार।
- एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में तीन दिवसीय विचार-विमर्श बैठक पूरी हुयी। समिति को अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले कई अहम सुझाव।
- वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन आज। उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों के करीब पांच सौ ग्राम प्रधान करेंगे प्रतिभाग।

केन्द्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वरुणा नदी के किनारे सिक्स लेन और फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को कल मंजूरी दे दी। तिरालीस किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर दस हजार नौ सौ अट्ठावन करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा।

“एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ-साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर है एम बोर्ड में डेवलप होगा और करीब-करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में कल सात महत्वपूर्ण फैसलों को स्वीकृति दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट सिक्स लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 14 हजार 448 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी।

गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट सिक्स लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का यह होगा 14,448 करोड़ रुपए का बनेगा।

केन्द्रीय कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट-

कैबिनेट ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैनुफेक्चरिंग इको सिस्टम को मजबूत बनाने के लिये सेमिकॉन टू-प्वाइंट जीरो को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के लिये यूरिया-दो हजार छब्बीस की राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने बासठ हजार पांच सौ करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल फोन मैनुफेक्चरिंग की स्कीम को भी स्वीकृति दी। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ‘भव्य काशी-सुगम काशी’ को समर्पित ये परियोजनाएं श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुगम बनाएंगी, यातायात को नई गति देंगी और पर्यटन, व्यापार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी।

भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही यह कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा।

कल देशभर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग-ऑफ समारोह आयोजित हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर और फुटवियर सहित दूसरे उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा।

अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवियर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाता था। यह शुल्क जीरो हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपेरल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो यह भी शुल्क जीरो हो जाएगा। इसमें 12 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाता था और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को तो वह बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस—दो हजार छब्बीस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोजगार और उद्यमिता से आत्मनिर्भर बने युवाओं को सम्मानित किया। समारोह में केंद्र सरकार के बारह वर्षों में प्रदेश में हुए कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका कौशलम का विमोचन भी किया गया। अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया।

सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्कूल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकॉनमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया।

एक राष्ट्र—एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय विचार—विमर्श बैठक कल सम्पन्न हो गयी। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों और विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। समिति ने प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने कहा कि अलग—अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले।

10 राज्यों में हम जा चुके हैं। जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई अलग—अलग सेक्टर के लोगों को हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमेटी इससे बहुत बेनिफिट हुई। कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम आप सब अपनी—अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरैस्ट में अच्छा होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वह हम पार्लियामेंट को रिक्मेंडेशन देंगे।

प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में बिजनौर जिले के सोलह अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना एजेंसी—साचीज के तीन सदस्यीय विशेष दल ने बिजनौर के बीस अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया था। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सोलह अस्पतालों में निर्धारित दिशा—निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पाया गया। इनमें से छह अस्पतालों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं और उनके भुगतान रोकने के आदेश दिए गए हैं। बाकी दस अस्पतालों को अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज पंच सम्मेलन का आयोजन होगा। एक रिपोर्ट—

सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के करीब 500 ग्राम प्रधान शामिल होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हिस्सा लेंगे। इस सम्मलेन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाना है। साथ ही इस सम्मेलन के जरिये वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों और उद्देश्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की समझ को भी मजबूत किया जाएगा। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार वाराणसी।

रुक—रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जल स्तर में बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं देवरिया में भी सरयू नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच, मौसम विभाग ने प्रदेश में आज कहीं कहीं बारिश, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने, गर्मी और उमस भरी स्थितियां बने रहने की संभावना जताई है।
